# क्या मोदी की COVID-19 फंड पहल SAARC को पुनर्जीवित करेगी?

लेखक- कल्लोल भट्टाचर्जी (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

20 मार्च, 2020

**"केवल मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और सहयोग ही इस क्षेत्र में विकास का सृजन कर सकता है।"**

रविवार को, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क, SAARC) के सदस्य देशों के नेताओं को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क के लिए एक नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) आपातकालीन कोष बनाने का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी का ये प्रस्ताव कई लोगों के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाला था, क्योंकि भारत सरकार कई वर्षों तक यह सुनिश्चित करती रही है कि सार्क आतंकवाद के क्षेत्रीय खतरे से निपटने में सफल नहीं रहा है। आखिरी सार्क शिखर सम्मेलन 2014 में काठमांडू में आयोजित किया गया था। इस्लामाबाद में होने वाला 19वां सार्क सम्मेलन 18 सितंबर, 2016 को उरी में भारतीय सैन्य अड्डे पर हमले के बाद रद्द कर दिया गया था। तब से भारत जोकि सबसे बड़ा सार्क देश है, ने माना है कि समूहीकरण में अंतर्निहित समस्याएं हैं और इसी वजह से उसने सार्क के विकल्प के रूप में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन (BIMSTEC) जैसे नए संगठनों की भूमिका पर अधिक ध्यान देना शुरू किया है। कल्लोल भट्टाचार्जी द्वारा संचालित एक बातचीत में मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अब्दुर राशिद और क़मर आगा ने सार्क की प्रासंगिकता पर चर्चा की, उसी का संपादित अंश इस आलेख में पेश किया जा रहा है:-

**क्या आपको लगता है कि श्री मोदी की पहल से सार्क को मदद मिलेगी?**

**मेजर जनरल अब्दुर रशीद:** खतरों के बारे में और इन धारणाओं के बारे में निश्चित रूप से इन देशों के बीच कई समानताएँ हैं। इस तरह की पहल का हमेशा स्वागत किया जाएगा। यह पहल आश्चर्यचकित करने वाला था क्योंकि सभी ने सोच लिया था कि सार्क का अस्तित्व अब खतम हो चुका है। लेकिन इस बार जब बैठक श्री मोदी द्वारा शुरू की गई, तो इसका स्वागत किया गया। बांग्लादेश के लोगों ने भी सकारात्मक रुख दिखाया है। इसके अलावा, ये सभी देश समस्या को लेकर चिंतित हैं। निश्चित रूप से हम इस मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इससे तनाव कम होगा और मजबूत सहयोग बनेगा।

**क़मर आगा:** मैं मेजर जनरल के तर्क का पूरा समर्थन करता हूँ। इस क्षेत्र को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से एकीकृत किया गया है। क्षेत्र के भीतर सदियों से पलायन हुआ है और हमेशा सभी देशों ने एक दूसरे का सहयोग किया है। इसमें ब्रिटिश शासन के बाद वीजा पासपोर्ट प्रणाली को शुरू किया गया था। हमने सोचा कि इससे सार्क देशों के बीच सहयोग विकसित होगा।

हमारे पास आम समस्याएँ हैं: न केवल COVID-19 बल्कि पानी के बँटवारे और गरीबी सहित अन्य बड़ी समस्याएँ भी हैं। अगर हम साथ आते हैं, तो इससे एक बार फिर सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

**इससे पहले स्वास्थ्य निधि के निर्माण जैसी पहल की कोशिश नहीं की गई थी, हालाँकि सार्क चार्टर ऐसे सहयोग का संकेत देता है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक सहयोगात्मक भावना की अनुपस्थिति को देखते हुए,**

**क्या सार्क में इस तरह की बड़ी समस्याओं को रोकने की भावना है?**

**मेजर जनरल अब्दुर रशीद:** सार्क में हर देश की चिंताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान को छोड़कर, आप देख सकते हैं कि BIMSTEC जैसे अन्य संगठन कैसे बढ़ रहे हैं क्योंकि हर देश वहाँ पर हर सहायता के लिए तत्पर है। सार्क के बारे में हमें यह देखना होगा कि सभी देश हमेशा तत्पर रहें और कोशिश करें कि एक साझा मंच बनाया जा सके। यह फंड एक अच्छा प्रस्ताव है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना इस ने प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया है।

**सार्क की प्रासंगिकता को लेकर चिंताएँ हमेशा बनी रही हैं, खासकर इस्लामाबाद में शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं होने के बाद। क्या आपको लगता है कि भारत-पाकिस्तान की समस्याएँ एक बार फिर से समूह के पुनरुद्धार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं?**

**क़मर आगा:** पाकिस्तान को यह महसूस करना चाहिए कि क्षेत्र का भविष्य भारत के सहयोग से ही जुड़ा है। भारत ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान सरकार का भी पाकिस्तान से निपटने का अनुभव कड़वा रहा है क्योंकि हमेशा से ये कहते आये हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहे हैं। फिर भी पाकिस्तान एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और इसलिए हम इस बात पर जोर देते हैं कि पाकिस्तान भी सहयोग के लिए तत्पर रहे।

**लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमें बार-बार विदेश मंत्री एस. जयशंकर सहित प्रमुख भारतीय नीति निर्माताओं और अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि सार्क में अंतर्निहित समस्याएँ हैं, तो क्या भारत का प्रयास एक ईमानदार प्रयास है?**

**मेजर जनरल अब्दुर रशीद:** सुरक्षा का मुद्दा इस क्षेत्र में काफी चिंता का विषय है और भारत-पाकिस्तान सुरक्षा स्थिति निश्चित रूप से सार्क को प्रभावित करती आई है, लेकिन भारत-बांग्लादेश सहयोग सुरक्षा प्रबंधन का एक बड़ा उदाहरण बन गया है। हम बांग्लादेश में भी आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के रवैये के बारे में काफी चिंतित हैं, क्योंकि उनके पास एक आंतरिक बल है जो हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इसलिए स्वचालित रूप से हमें इस पर (सार्क में) हर देश की चिंता को ध्यान में रखना होगा। मुझे यकीन है कि अगर हम एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का निर्माण कर सकते हैं, तो दक्षेस उच्चतर स्थिति प्राप्त कर सकता है। अगर हम संदेह और भरोसे की कमी के साथ रहेंगे तो विकास उल्टा हो जाएगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने भी सीखा है कि संघर्ष और तनाव देश को आगे नहीं ले जा सकते। फिलहाल, बांग्लादेश विकास योजनाओं के साथ आगे बढ़ा है और उसने दिखाया है कि भारत के साथ संबंध आगे बढ़ सकते हैं।

**पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के हालिया बयान के मद्देनजर, जिसने संकेत दिया कि देश संकट से निपटने के लिए तैयार नहीं है, यह पूछना स्वाभाविक है कि क्या पाकिस्तान सार्क सहयोग के लिए और इसके पुनरुद्धार के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाएगा?**

**क़मर आगा:** मुझे लगता है कि समस्या इतनी बड़ी है कि कोई भी देश इसे अकेले नहीं संभाल सकता। पाकिस्तान की सीमा ईरान से भी जुड़ी है और यह पूरे क्षेत्र के लिए एक आम समस्या है। पाकिस्तान में समस्या यह है कि चुनी हुई सरकार ने परंपरागत रूप से भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की है। लेकिन सभी नेताओं (चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो बेनजीर भुट्टो या नवाज शरीफ हों) को कई बड़े समस्याओं का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान अभी भी हमसे निपटने के लिए अनिच्छुक हैं लेकिन हालात इस मुद्दे पर पाकिस्तान को कम से कम सहयोग करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दूसरा, वे अपने ही देश में एक बहुत गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। पहले वे तेल-समृद्ध देशों से धन प्राप्त करते थे, लेकिन तेल की कीमतें गिर गई हैं और इन देशों के पास यमन में युद्ध जैसी मुसीबतें भी हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर निर्भर है, लेकिन यह भी लंबे समय तक नहीं चल सकता क्योंकि चीन-यू.एस. संबंध भी विकसित हो रहे हैं। इसलिए 1990 के दशक जैसी स्थिति, जब सहयोग संभव था, इस बार भी यह संभावना प्रबल होते दिख रही है और बाद में संबंधों का सामान्यीकरण भी संभव हो सकता है।

**अन्य समस्याएँ हैं जो सार्क के सदस्य देशों के बीच उभर रही हैं जैसे भारत में एक देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का प्रस्ताव। इससे बांग्लादेश में चिंता बढ़ गई है। नेपाल के साथ मधेसी मुद्दा और कालापानी में सीमा विवाद भी है। क्या सार्क की पुनरुद्धार योजना इन चुनौतियों से पार पा सकती है?**

**मेजर जनरल अब्दुर रशीद:** भारत एक बड़ा पड़ोसी है, इसलिए स्वचालित रूप से सभी छोटे देश जो इसकी सीमा से सटे हैं, उन्हें इसके बारे में कुछ चिंताएँ होंगी। इसलिए, भारत से अपने छोटे पड़ोसियों की चिंताओं पर ध्यान देने के लिए सहयोग बहुत महत्त्वपूर्ण है।

बांग्लादेश के दृष्टिकोण से, हमने भूमि सीमा समझौते (LBA) को हल कर दिया है और परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान किया है। हमने बड़ी संख्या में लोगों को निराश किए बिना इसे बहुत शांति से आगे बढ़ाया है। इसकी तुलना में 1947 एक मानवीय आपदा थी, जहाँ सवाल जीवन के विस्थापन से जुड़ा था। हमने यह सिद्ध किया है कि हम भारत के साथ द्विपक्षीय समस्याओं को हल कर सकते हैं। सभी सार्क देशों की भारत के साथ इस तरह के मतभेदों को दूर करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति होनी चाहिए। बांग्लादेश का कहना है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम भारत का आंतरिक मामला है। जब हम पर असर पड़ेगा तो बांग्लादेश जवाब देगा।

सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सरकार से सरकार का सहयोग पर्याप्त नहीं है। अधिक लंबे समय तक चलने वाली चीज लोगों से लोगों के बीच संबंध होती है। इसमें भारत और बांग्लादेश का संबंध भारत और पाकिस्तान से कहीं आगे है। यह सिर्फ भारत के साथ ही नहीं बल्कि म्यांमार के साथ भी है।

सुश्री हसीना ने रोहिंग्या मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया है। अगर भारत छोटे पड़ोसियों का समर्थन करने के लिए इन आदर्शों और मानसिकता का अनुकरण कर सकता है, तो हम एक शांतिपूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं।

**क्या आपको लगता है कि NRC और CAA जैसे मुद्दे सार्क के लिए बाधा पैदा कर सकते हैं?**

**क़मर आगा:** CAA एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि इसमें कुछ आंतरिक विरोध भी निहित हैं। पाकिस्तान को छोड़कर अन्य सार्क देशों ने स्वीकार किया है कि यह भारत का आंतरिक मामला है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का संबंध है सुरक्षा मुद्दा महत्त्वपूर्ण रहेगा। इन मतभेदों से निपटने के लिए हमारे पास बिम्सटेक और द्विपक्षीय संलग्नक जैसे संगठन हैं। पाकिस्तान को छोड़कर इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ, भारत के अब तक संबंध अच्छे रहे हैं। पाकिस्तान उग्रवाद की मदद से अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति खराब है और विदेशी निवेश नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसी संभावना है कि पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल में ब्लैकलिस्ट पर रखा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि सार्क सम्मेलन इस्लामाबाद में या एक वैकल्पिक स्थान पर होगा।

**जब किसी संगठन का कुछ समय के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, तो वह अपनी ताकत खो देता है। यह सार्क के लिए भी सही है। दक्षेस को बढ़ावा देने के लिए अब क्या किया जा सकता है?**

**मेजर जनरल अब्दुर रशीद:** सार्क कुछ समय के लिए कमजोर प्रतीत हो रहा था। SAARC के बाद, हमने BBIN [बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल], BIMSTEC] BCIM [बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार आर्थिक गलियारा] शुरू किया था। बांग्लादेश समान रूप से पाकिस्तान के आतंकवादी तत्त्वों के संरक्षण के बारे में चिंतित है। जैश-ए-मोहम्मद बांग्लादेश में भी संगठनों का समर्थन करता है और उस मोर्चे पर हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए, हमें विश्वास बनाने की जरूरत है और पाकिस्तान को पहली प्रतिबद्धता देनी होगी कि वह इन अनैतिक ताकतों का समर्थन नहीं करे। जैसा कि यहाँ चर्चा की गई है, पाकिस्तान में एक अद्वितीय सिविल-मिलिट्री समस्या भी है। लेकिन बांग्लादेश ने अपनी सेना पर राजनीतिक नियंत्रण रखने और विकास पर ध्यान केंद्रित करने का रास्ता दिखाया है और इसीलिए हम बेहतर स्थिति में हैं। हमें इन मुद्दों को सौहार्दपूर्वक हल करना होगा। LBA और समुद्री सीमा समझौतों ने भी SAARC के लिए रास्ता दिखाया है। दक्षेस के भीतर लोगों से लोगों के संपर्क में मदद करने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा देना चाहिए।

**COVID-19 संकट से परे इस समय भारत सार्क को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकता है?**

**क़मर आगा:** वैश्वीकरण के युग में अकेला कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। आर्थिक एकीकरण और विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक और शैक्षिक विकास और एकीकरण का समर्थन करना कुछ महत्त्वपूर्ण चीजें हैं, जो भारत कर सकता है। भारत म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड के साथ संपर्क विकसित कर रहा है। इसी तरह हमने पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी की माँग की लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम चाबहार में इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं जिन्हें सार्क में आगे बढ़ाने की जरूरत है।

## संभावित प्रश्न ( प्रारंभिक परीक्षा )

**प्र. हाल ही में भारत ने सार्क देशों के लिए कोरोना वायरस ( COVID-19 ) आपातकालीन कोष की स्थापना करने की पहल की है। इस संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. भारत ने इस कोष में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है।
2. इस पहल से भारत और सार्क देशों के संबंधों में सुधार होगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं।

## Expected Questions (Prelims Exams)

**Q. Recently India has taken an initiative to set up Corona Virus (COVID-19) Emergency Fund for SAARC countries. Consider the following statements in this context:**

1. India has contributed US $ 2 billion to this fund.
2. This initiative will improve relations between India and SAARC countries.

Which of the above statements are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Both 1 and 2 (d) None of these

**नोट : 19 मार्च को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा ( संभावित प्रश्न ) का उत्तर 1 (d) होगा।**

## संभावित प्रश्न ( मुख्य परीक्षा )

**प्र. हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सार्क को कोविड-19 से लड़ने के लिए एक सामूहिक मंच बनाने का प्रयास सार्क को पुनर्जीवित करने में कितना सहायक हो सकता है? ( 250 शब्द )**

**To what extent Prime Minister Modi's attempt to make SAARC a collective platform to fight COVID-19 recently could be helpful in reviving SAARC? (250 words)**

**नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।**